नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

यूसीसी पर जनसंवाद पूरा : मुख्यमंत्री

300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण

166 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती

- इंदौर में 83 करोड़ के जिला अस्पताल का लोकार्पण
- पश्चिमी इंदौर को मिला नया जिला अस्पताल

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 15 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय के लोकार्पण अवसर पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में एक समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके लिए व्यापक जनसंवाद की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है. मुस्लिम बहनें भी हमारी बहन हैं, उनके हितों और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.'

उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा-370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया है और अब मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में जाकर सुझाव लिए हैं, जिनके आधार पर सरकार आगे की प्रक्रिया तय कर रही है.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 83.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित चार मंजिला 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया. यह अस्पताल पश्चिमी इंदौर की लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को काफी हद तक पूरा करेगा.

हालांकि अस्पताल की सभी सेवाएं एक साथ शुरू नहीं होंगी. पहले चरण में 34 बिस्तरों वाली मातृ एवं प्रसूति इकाई शुरू की गई है, जबकि मेडिसिन, सर्जरी, अस्थि रोग और अन्य विशेषज्ञ विभागों का संचालन चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा.

दो दशक पुराने इंतजार के बाद मिला अस्पताल

धार रोड क्षेत्र में संचालित जिला अस्पताल वर्षों से पुराने और सीमित संसाधनों वाले भवन में काम कर रहा था. बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को देखते हुए नए अस्पताल का प्रस्ताव वर्षों पहले भेजा गया था. लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्माण कार्य में हुई देरी के बाद अब यह परियोजना मूर्त रूप ले सकी है.

लागत में चार गुना से अधिक बढ़ोतरी

परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 18 करोड़ रुपये थी, लेकिन समय के साथ तकनीकी बदलाव, अतिरिक्त निर्माण कार्य और संशोधित स्वीकृतियों के कारण खर्च बढ़कर 83.16 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसके बावजूद अस्पताल की सभी सेवाएं फिलहाल शुरू नहीं हो पा रही हैं. अस्पताल के संचालन के लिए 166 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है. इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. प्रशासन का दावा है कि आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होते ही अस्पताल की शेष सेवाएं भी आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएंगी.

भोपाल में कांग्रेस की 200 किमी 'जेन जी' साइक्लोथॉन का समापन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 15 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'युवा स्वाभिमान : 'जेन जी' साइक्लोथॉन' का बुधवार को भोपाल में समापन हुआ. इंदौर से शुरू हुई इस यात्रा ने लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय की और समापन अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा, रोजगार तथा छात्रों के अधिकारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया.

यात्रा के दूसरे दिन साइक्लोथॉन आष्टा से प्रारंभ होकर कोठरी, अमलई, सोंडा, गुढ़भेला, सीहोर, फंदा टोल नाका तथा भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए रॉयल मार्केट पहुंची, जहां एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई. समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि यह साइक्लोथॉन शिक्षा, रोजगार और युवाओं के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार परीक्षा अनियमितताओं, सरकारी स्कूलों के बंद होने और बढ़ती बेरोजगारी ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है. उन्होंने कहा कि छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह अभियान राहुल गांधी की राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' पहल का हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि दो दिनों में दो लाख से अधिक लोगों ने साइक्लोथॉन में भाग लिया. पटवारी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने छात्रों का विश्वास तोड़ दिया है. उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मामलों का एक माह के भीतर निराकरण हो और दोषियों को कठोर दंड दिया जाए.

कार्यक्रम के अंत में जीतू पटवारी ने विरोध स्वरूप पुलिस अधिकारियों से कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने की बात कही. हालांकि प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए किसी भी गिरफ्तारी के बिना प्रतिभागियों को जाने दिया.

पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी

- तलेन थाना क्षेत्र में दोहरे मौत कांड से हड़कंप
- पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

तलेन, 15 जुलाई . राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के ग्राम फूलपुरा में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार, पति ने पहले अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या की और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 48 वर्षीय सुशीला लवंशी रोज की तरह खेत स्थित मकान पर रह रहे अपने पति रायसिंह उर्फ बालकनाथ (50) को खाना देने गई थीं. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और रायसिंह ने पत्नी पर चाकू से 15 से 20 वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने मकान के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

शाम को जब बेटा नवीन काम से घर लौटा तो मां के घर नहीं पहुंचने और मोबाइल बंद मिलने पर उसने तलाश शुरू की. खेत स्थित मकान का दरवाजा अंदर से बंद मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां सुशीला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं, जबकि रायसिंह फंदे से लटका मिला.

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. तलेन में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं होने के कारण दोनों शवों को बुधवार सुबह पचोर भेजा गया, जहां देर शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपे गए. पुलिस का कहना है कि मामले में पारिवारिक विवाद, मानसिक स्थिति समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कुल आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर केंद्रित रही बहस

जबलपुर. हाइकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में मेरिट पर नियमित सुनवाई शुरू की. पहले दिन आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने से आरक्षण की 50 प्रतिशत संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता है.

पहले दोषी तय करें, फिर नया बजट दें : हाईकोर्ट

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की सांख्य सागर झील में सीवर का पानी पहुंचने के मामले में राज्य सरकार और अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है.

कोर्ट ने कहा कि जब तक पहले खर्च किए गए 111 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक इस काम के लिए 191.24 करोड़ रुपए का नया बजट मांगने का कोई औचित्य नहीं है. कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को 27 जुलाई को सीलबंद रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में झील को बचाने और सीवर रोकने के लिए 191.24 करोड़ रुपए के नए बजट की सिफारिश की गई थी. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीवरेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले ही 111 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ.

कोर्ट ने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि 111 करोड़ रुपए की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है. जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक नए बजट पर विचार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोषी अधिकारियों की सूची और पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं.

ग्वालियर में स्थापित होगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

ग्वालियर, 15 जुलाई। ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया गया है।

जिले में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के अधिपत्य वाली 100 एकड़ भूमि को वापस लेकर राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी किया गया है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, पूर्व में साडा को विकास योजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटित की गई थी. म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की मांग पर इस भूमि में से औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मप्र शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में अनापत्तिप्रदान किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

जमीन विवाद में भाइयों में खूनी संघर्ष, एक की मौत

- दो हुए गंभीर रूप से घायल, भोपाल रेफर

रायसेन,15 जुलाई. जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर गौहरगंज थाना क्षेत्र के चिकलोद कला पुलिस चौकी के नगरी गांव के पास खेत में बोवनी के दौरान मंगलवार की शाम को को दो सगे भाइयों में एवं उनके परिवार के सदस्यों में कहासुनी के दौरान कुछ ही देर में चाकूबाजी शुरू हो गई.

जिसमें एक भाई को चाकू लगने से उसकी मौत हो गई ओर मृतक के दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए , जिन्हें भोपाल रेफर किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक ने बताया कि पैतृक भूमि पर बोवनी करते समय दो सगे भाई विष्णु प्रसाद सेन एवं नारायण सेन के बीच विवाद हो गया. जिस पर नारायण सेन एवं उसके पुत्रों द्वारा विष्णु प्रसाद सेन एवं उनके दो पुत्र अखिलेश सेन अजय सेन पर चाकूओं से हमला कर दिया.

प्राणघातक हमले में विष्णु प्रसाद सेन की रीड की हड्डी में चाकू लगने से उनकी मौत हो गई.जबकि उनके पुत्र अखिलेश सेन एवं अजय सेन गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें भोपाल रेफर किया गया है.

योजना रीवा में पीआईबी का मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम संपन्न

आयुष्मान योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर : शुक्ल

रीवा, 15 जुलाई. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भोपाल द्वारा रीवा में आयोजित मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार ने गरीबों को नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दुनिया का सबसे बड़ा और सफल प्रयास किया है.

उन्होंने कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिली है और अब उन्हें महंगे उपचार की चिंता नहीं रहती. उन्होंने मीडिया से अपील की कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र हितग्राही इसका पूरा लाभ उठा सकें.

कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं में मौजूद विसंगतियों को दूर कर उन्हें अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, रीवा परिसर के प्रभारी डॉ. सत्येंद्र डेहरिया ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य योजना और विकसित भारत-2047 जैसे कार्यक्रम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ मीडिया की सकारात्मक भूमिका के कारण बड़ी संख्या में लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं.